# रेल बजट 2012-13 की मुख्य विशेषताएं

## ध्यान देने योग्य तथा दीर्घकालिक लक्ष्य

1. संरक्षा; 2. सुदृढ़ीकरण; 3. भीड़-भाड़ को कम करना तथा क्षमता संवर्धन; 4. आधुनिकीकरण; 5. 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में परिचालन अनुपात को 95 प्रतिशत से घटाकर 74 प्रतिशत करना।

## प्रस्तावित उपाय

- काकडोकर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में एक सांविधिक नियामक निकाय के रूप में रेलवे संरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करना।
- आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए सैम पित्रोदा समिति द्वारा यथा संस्तुत मिशनों की स्थापना करना।
- काकोडकर और पित्रोदा समितियों द्वारा चिह्नित किए गए पांच ध्यान देने वाले क्षेत्रों अर्थात् (क) रेलपथ (ख) पुल (ग) सिगनल एवं दूरसंचार प्रणाली (घ) चल स्टॉक और (ड.) स्टेशनों तथा माल टर्मिनल पर वार्षिक निवेश योजना को संतुलित करना।
- नए बोर्ड सदस्य (संरक्षा/अनुसंधान) की नियुक्ति करना।
- समपारों को समाप्त करने के लिए रेल-रोड ग्रेड सैपरेशन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना करना।
- प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए योजना आवंटन प्रदान करना ताकि तय अवधि के अंदर कार्यों को पूरा कर फायदा उठाया जा सके।
- आपदा प्रबंधन के लिए कौशल का विकास करने के लिए बेंगलूरू, खड़गपुर और लखनऊ में तीन 'संरक्षा विलेज़ों' की स्थापना करना।

## संसाधन जुटाना

- सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से स्टेशनों का पुनर्विकास करने के लिए इंडियन रेलवे डेवलेपमेंट कार्पोरेशन की स्थापना करना।
- मौजूदा रेलवे माल शेडों और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास और प्रबंधन के लिए लॉजिस्टक्स कार्पोरेशन की स्थापना करना।
- वैगन लीजिंग, साइडिंग, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, कंटनेर ट्रेन परिचालन, रेल संपर्क परियोजानाओं (आर3i और आर2सी-i) के लिए निजी निवेश योजनाओं को पीपीपी साझेदारों के लिए और भी आकर्षक बनाया जा रहा है।
- नए बोर्ड सदस्य (पीपीपी/मार्केटिंग) की नियुक्ति की जाएगी।

## महानगरीय परियोजनाएं

- कोलकाता मेट्रो के लिए पिछले वर्ष घोषित कार्यों की प्रगति संतोषजक है और नए खंडों को शामिल करने के लिए कुछ परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है।
- एमएमटीएस के वाणिज्यिक प्रबंधन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक एसपीवी की स्थापना की जाएगी।

- सीएसटीएम-पनवेल और विरार-वसई-दीवा-पनवेल खंडों पर तीव्र मार्गों के निर्माण के लिए मुम्बई रेल विकास निगम द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा।
- हार्बर लाइन पर 12 कार रेकों को चलाने के लिए अपेक्षित कार्य शुरू करना।
- पीपीपी के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के साथ चर्चगेट से विरार तक उत्थापित रेल गलियारे की वित्तीय संरचना को मूर्त रूप देना।
- छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और कल्याण के बीच इसी तरह के एक और गलियारे के पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण करना।
- राष्ट्रीय उच्च रफ्तार रेल प्राधिकारण को स्थापित करना।
- छः उच्च रफ्तार वाले गलियारों के लिए पूर्व व्यावहारिकता अध्ययन पहले ही पूरा कर लिया गया है; दिल्ली-जयपुर-अजमेर-जोधपुर खंड के संबंध में अध्ययन वर्ष 2012-13 में किया जाना है।

**राज्य सरकार के साथ सहयोग**

- यात्रियों और माल यातायात के संचलन के लिए राज्य में तीन रेल कॉरिडोरों को विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं:
- राज्य सरकारों के योगदान से 10 राज्यों में 5,000 किमी से अधिक लंबाई की 31 परियोजनाओं को निष्पादित किया जा रहा है।
- हरियाणा, आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की सरकारों के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर चार परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है।
- कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान एवं महाराष्ट्र सरकारों के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर 12 परियोजनाओं को योजना आयोग के अनुमोदन के लिए भेजा गया है।
- शुरू से लेकर अंत तक संपर्क मुहैया कराने के लिए 17 परियोजनाओं को सक्रियता से स्वीकृत किया गया और अन्य 28 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है।

**पड़ोसी देशों के साथ संपर्क**

- नेपाल से संपर्क मुहैया कराने के लिए जोगबनी-बिराटनगर और जयनगर-बिजलपुरा-बरडीबस नई लाइन के निर्माण का कार्य पहले ही प्रगति पर है।
- अगरतला को बांग्लादेश के अखौरा से जोड़ने वाली एक परियोजना को 2012-13 में शुरू किया जाना है।

**रेल आधारित उद्योग**

- 2011-12 में छपरा के रेल पहिया संयंत्र ने 78 पहियों का उत्पादन किया; यह संयंत्र 2012-13 में पूरी तरह चालू हो जाएगा।
- 2011-12 में रायबरेली सवारी डिब्बा कारखाने ने 10 सवारी डिब्बों का उत्पादन किया; कारखाने का दूसरा चरण 2012-13 में शुरू किया जाएगा।

- दानकुनी स्थित डीजल कम्पोनेन्ट कारखाने ने ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और 2012-13 में इसे पूर्ण रूप से चालू कर दिया जाएगा।
- कुल्टी स्थित माल डिब्बा निर्माण कारखाना और बज बज स्थित फिएट बोगी फ्रेम यूनिट का उत्पादन 2012-13 में शुरू हो जाएगा।
- एक माल डिब्बा कारखाने को सीतापल्ली (ओडिशा के गंजम जिले से) में स्थापित किया जाना है।
- पालघाट में केरल सरकार के सहयोग से एक रेल सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित किया जाना है; राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से गुजरात में कच्छ क्षेत्र में और कर्नाटक के कोलार में सवारी डिब्बों के लिए दो अतिरिक्त नई निर्माण इकाइयों को स्थापित किया जाना है।
- उच्च अश्व शक्ति डीजल इंजनों के लिए ट्रैक्शन अल्टरनेटरों के निर्माण के लिए एक संयंत्र, मध्यप्रदेश के विदिशा में स्थापित किया जाना है।
- उच्च शक्ति वाले विद्युत इंजनों में प्रयोग के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी वाले प्रोपल्शन सिस्टम के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल के श्यामनगर में एक फैक्टरी की स्थापना।
- लोकोमोटिव शैलों के फैब्रीकेशन और नई पीढ़ी के 9,000 एचपी इंजनों के निर्माण के लिए 3 फेज़ इंजनों की असेंबली हेतु दानकुनी में चितरंजन रेल इंजन कारखाना की विद्युत इंजन सहायक इकाई का आवर्धन।
- रेलवे द्वारा अधिगृहीत रुग्ण मालडिब्बा इकाई 'ब्रेथवेट' को बोर्ड ऑफ रिकन्सट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज द्वारा टर्न अराउंड अवार्ड से सम्मानित किया गया।

**हरित पहल**

- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 72 मेगावाट क्षमता वाले विंड मिल प्लांटों की स्थापना।
- दूर दराज स्थित 200 रेलवे स्टेशनों को हरित ऊर्जा स्टेशनों की स्थापना, जो पूर्णरूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर होंगे।
- 1,000 चौकीदार वाले समपार फाटकों पर सौर प्रणाली आधारित प्रकाश व्यवस्था करना।
- डीजल रेल इंजनों के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए मोबाइल उत्सर्जन परीक्षण कारों को अपनाना।
- रायपुर और टोंडियारपेट में दो बॉयो-डीज़ल संयंत्रों को चालू करना।
- उत्तरी बंगाल के सुंदर जंगलों से होकर गुजरने वाली "ग्रीन ट्रेन" चलाना।
- 2500 सवारी डिब्बों में बॉयो-टॉयलेट लगाया जाना।

**यात्रियों/रेल उपयोगकर्त्ताओं के लिए सुविधाएं**

- महत्वपूर्ण स्टेशनों पर 321 एस्केलेटरों को लगाना, जिनमें से 50 एस्केलेटर 2012-13 में चालू किए जाएंगे।

- 12 अत्याधुनिक मशीनीकृत लॉंड्रियां पहले ही स्थापित कर दी गई हैं और 2012-13 के दौरान 6 और लॉंड्रियां कार्य करना शुरू कर देंगी।
- ई-टिकट के मामले में यात्री के मोबाइल फोन पर एसएमएस को वैध आरक्षण के प्रमाण के रूप स्वीकार करना।
- किफायती दरों पर क्षेत्रीय भोजन की शुरूआत; एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से भोजन के बहुत से विकल्प मुहैया कराने के लिए बुक-ए-मील योजना शुरू करना।
- महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एसी एक्जीक्यूटिव लाऊंजों की स्थापना करना।
- तमिलनाडु में पानूर में और महाराष्ट्र में अंबरनाथ में नए रेल नीर संयंत्रों की स्थापना।
- गाड़ियों में हाउस-कीपिंग सेवाओं का विस्तार करना।
- राजधानी, शताब्दी और दुरांतों गाड़ियों में ऑन-बोर्ड रेल बंधु मैगजीन शुरू करना।
- सिक्का/करंसी चालित टिकट वैंडिंग मशीनों को शुरू करना।
- प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को अल्टरनेट गाड़ियों में जगह उपलब्ध कराने के लिए अल्टरनेट ट्रेन एकोमंडेशन सिस्टम शुरू करना।
- विश्व-स्तरीय इंटीरियर डिजाइन युक्त मॉडल रेक शुरू करना।
- 2012-13 में प्रस्तावित 84 स्टेशनों सहित 929 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में अपग्रेड करना; अब तक 490 स्टेशनों के उच्चीकरण का कार्य पूरा हो गया है।
- 24 स्थलों पर बहु-कार्यात्मक परिसरों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।
- 151 डाक घरों के माध्यम से पीआरएस टिकटों की बिक्री करना।
- माल यातायात के लिए रेलवे रसीद के इलैक्ट्रोनिक ट्रांसमिशन को कार्यान्वित करना।
- यात्रियों को एसएमएस, इंटरनेट आदि के माध्यम से ट्रेन रनिंग की सूचना देने के लिए सैटेलाइट आधारित रियल टाइम ट्रेन इन्फार्मेशन सिस्टम (सिमरन) शुरू करना।
- ऑन बोर्ड पैसेंजर डिस्पले प्रणाली शुरू करना जिसमें अगले हाल्ट स्टेशन और आगमन के संभावित समय की सूचना उपलब्ध होगी।
- प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में अलग तरह से सक्षम व्यक्तियों को ध्यान में रखकर विशेष रूप से निर्मित सवारी डिब्बे लगाए जाएंगे।
- पैंट्री कारों और बेस किचनों के लिए प्रतिष्ठित व्यावसायिक एजेंसियां नियुक्त करना।
- स्टेशनों और रेलगाड़ियों में साफ-सफाई के लिए स्पैशलाइज्ड हाउस-कीपिंग बॉडी की स्थापना करना।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद में समर्पित रेलवे डिजाइन केन्द्र की स्थापना करना।

**कोचिंग टर्मिनल**

- नेम्मम, कोट्टायम, मऊ और दानकुनी में नए कोचिंग टर्मिनलों के लिए सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करना।
- तमिलनाडु में रोयापुरम स्टेशन के विकास के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन, जिसके लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

- सिडको के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार के साथ भागीदारी में पनवेल में नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स और कालाम्बोली में कोच अनुरक्षण परिसर की योजना बनाई गई है।
- ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के 175वें जन्म शताब्दी की स्मृति में उनके जन्म स्थल नैहाटी में नया कोचिंग टर्मिनल।

**वार्षिक योजना 2012-13**

- 60,100 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक योजना परिव्यय
  - 24,000 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता
  - 2,000 करोड़ रुपये का डीजल उपकर
  - आंतरिक संसाधनों से 18,050 करोड़ रुपये
  - 15,000 करोड़ रुपये का बाजार ऋण; पीपीपी- 1,050 करोड़ रुपये।
- 2012-13 में 725 किलोमीटर नई लाइनें बिछाने, 700 किलोमीटर का दोहरीकरण करने, 800 किलोमीटर का आमान परिवर्तन करने और 1100 किलोमीटर का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई लाइनों के लिए 6,872 करोड़ रुपये, दोहरीकरण के लिए 3,393 करोड़ रुपये, आमान परिवर्तन के लिए 1,950 करोड़ रुपये और विद्युतीकरण के लिए 828 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं।

**वित्तीय निष्पादन 2011-12**

- लदान लक्ष्य में 23 मिलियन टन की कमी करके इसे 970 मिलियन टन किया गया।
- संशोधित अनुमानों में सकल यातायात प्राप्तियां 1,03,917 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, इनमें बजट अनुमानों की तुलना में 2,322 करोड़ रुपये की कमी आई।
- साधारण संचालन व्यय के लिए 75,650 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया जो बजट अनुमानों से 2,000 करोड़ रुपये अधिक है, पेंशन भुगतान में भी 1,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।
- मौजूदा लाभांश देयता का पूरा भुगतान किया जाएगा।
- 5,258 करोड़ रुपये की बजट राशि की तुलना में 1,492 करोड़ रुपये का आधिक्य हुआ।
- विकास निधि के तहत संरक्षा संबंधी कार्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय से 3,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया।
- परिचालन अनुपात बजट अनुमानों के 91.1 प्रतिशत की तुलना में 95.0 प्रतिशत रहा।

**बजट अनुमान 2012-13**

- 1,025 मिलियन टन का माल लदान, जो 2011-12 की तुलना में 55 मिलियन टन अधिक है।
- यात्रियों में वृद्धि 5.4 प्रतिशत है।
- सकल यातायात प्राप्तियां 1,32,552 करोड़ रुपये अर्थात् 2011-12 के संशोधित अनुमान की तुलना में 27.6% वृद्धि।

- साधारण संचालन व्यय  84,400 करोड़ रुपये।
- मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 9,500 करोड़ रुपये और पेंशन निधि में 18,500 करोड़ रुपये का विनियोग।
- लाभांश का भुगतान करने के लिए 6,676 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 2011-12 में लिए गए 3,000 करोड़ रुपये के ऋण की पूरी राशि का ब्याज सहित भुगतान करना।
- परिचालन अनुपात 84.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

**सुरक्षा**

- सभी 202 चिन्हित स्टेशनों पर इंटीग्रेटिड सुरक्षा प्रणाली संस्थापित करने का कार्य 2012-13 में पूरा किया जाना है।
- रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अब 3500 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाएगा।
- रेलवे सुरक्षा बल हेल्पलाइन को अखिल भारतीय पैसेंजर हेल्पलाइन में समाहित करना।

**कर्मचारी कल्याण**

- रेलवे कर्मचारियों के लिए उनके कार्यस्थलों पर संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करना।
- रनिंग क्रू सहित कुशल और तकनीकी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त विश्राम सुनिश्चित करना।
- एनआईडी से कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपयुक्त वर्दी डिजाइन कराना।

**प्रशिक्षण और भर्ती**

- 2011-12 में 80,000 से अधिक लोगों को भर्ती किया गया।
- 2012-13 में एक लाख से अधिक लोगों को भर्ती किया जाना है- एससी/एसटी और ओबीसी के बैकलॉग को समाप्त करना।

**खेल-कूद**

- 2011-12 में रेलवे के 7 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाज़ा गया।
- रेलवे के 5 खिलाड़ियों ने ओलंपिक 2012 के लिए क्वालीफाई किया है।
- रेलवे खेलों के लिए रोड मैप तैयार करना।
- "रेल खेल रत्न" पुरस्कारों की शुरूआत, जो प्रत्येक वर्ष 10 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे।

**रियायतें**

- ट्रैवलर्स को दी गई रियायत का मूल्य प्रति वर्ष 800 करोड़ रु.  से अधिक है।

- "एप्लास्टिक अनैमिया" और "सिकल सैल अनैमिया" से पीड़ित रोगियों के लिए एसी 2, एसी 3, चेयर कार और स्लीपर क्लास के किराये में 50% रियायत।
- अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को राजधानी और शताब्दी गाड़ियों में यात्रा करने की सुविधा देना
- "इज्ज़त योजना" के अंतर्गत यात्रा दूरी 100 किमी. से बढ़ाकर 150 किमी. की गई है।

**उपनगरीय सेवाएं**

- मुंबई उपनगर में 75 अतिरिक्त गाड़ियां चलाना।
- चेन्नै क्षेत्र में 18 अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जानी है।
- कोलकाता क्षेत्र में 44 नई उपनगरीय गाड़ियां चलाई जानी हैं।
- 2012-13 में कोलकाता मैट्रो में 50 नई गाड़ियां चलाई जानी हैं।

**रेलगाड़ियां**

- 75 नई एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू की जानी हैं।
- 21 नई पैसेंजर गाड़ियां, 9 डेमू गाड़ियां और 8 मेमू गाड़ियां शुरू की जानी हैं।
- 39 रेलगाड़ियों का विस्तार किया जाना है।
- 23 रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि की जानी है।

**टैरिफ प्रस्ताव**

- रेलवे दर-सूची नियामक प्राधिकरण की स्थापना किए जाने पर विचार किया जाएगा।
- उपनगरीय और साधारण द्वितीय श्रेणी के यात्री किरायों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर; मेल/एक्सप्रेस द्वितीय श्रेणी में 3 पैसे प्रति किलोमीटर; स्लीपर श्रेणी में 5 पैसे प्रति किलोमीटर, एसी चेयर कार; एसी 3 और प्रथम श्रेणी में 10 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि; एसी 2 में 15 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी 1 में 30 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि।
- यात्री किरायों को अगले निकटतम 5 रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
- न्यूनतम किराए और प्लेटफार्म टिकट की कीमत अब 5 रुपये होगी।
- किराए में फ्यूल एडजस्टमेंट कम्पोनेंट (एफएसी) विचाराधीन।

*******